उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

7 फरवरी, 2018 • वर्ष 1, अंक 3

सात दिन – सात पृष्ठ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 31 जनवरी को उनके सरकारी आवास पर ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ ने भेंट की

- खादी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार
- कीटनाशकों के उपयोग पर अनुदान
- दिव्यांगजनों का पुनर्वासन एवं सशक्तिकरण
- सीरगोवर्धन बनेगा तीर्थ स्थल
- शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन
- बेहतर चिकित्सा सुविधाओं पर जोर

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

> मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि दिमागी बुखार से बचने के लिए पूरी तैयारी समयबद्ध ढंग से कर ली जाए। वैक्सीनेशन का कार्य मार्च अप्रैल 2018 तक अवश्य पूरा कर लिया जाए। जे.ई. और ए.ई.एस. वेक्टर जनित रोग हैं, इसलिए इनकी रोकथाम के लिए प्रभावित जनपदों में टीकाकरण के साथ-साथ गांवों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के अतिरिक्त इसके विरुद्ध लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार की भी आवश्यकता है। इस कार्य के लिए शिक्षण संस्थान व स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इससे जोड़े जाने की जरूरत है।

बेहतर चिकित्सा सुविधाएं
प्रदेश सरकार का लक्ष्य

जनता को गुणवत्तापरक चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। जनजागरण और जनसहभागिता के माध्यम से जनस्वास्थ्य की गंभीर चुनौतियों पर विजय प्राप्त की सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूनीसेफ और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित होने वाले 'दस्तक' जे.ई./ए.ई.एस. संचार अभियान के शुभारम्भ कार्यक्रम के अवसर पर संचार सामग्री, स्वच्छता किट व डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म की सीडी का विमोचन कर यह विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर अपने उद्बोधन में योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 38 जनपद एक्यूट इंसेफेलाइटिस (ए.ई.एस.) तथा जापानी इंसेफेलाइटिस (जे.ई.) से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

इंसेफेलाइटिस के उपचार में बचाव का सबसे अधिक महत्व है। यदि हम स्वच्छता की आदत अपना लें तो यह बीमारी स्वत: ही समाप्त हो सकती है।

वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से ही प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सका है। इसके दृष्टिगत 617 गांवों में सघन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

कुपोषण इस बीमारी का एक कारण है। इसलिए गर्भवती महिलाओं व नवजात बच्चों को पुष्टाहार व जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है। इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं को इन रोगों के सम्बन्ध में जागरूक किया जाएगा तथा उनके पोषण की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। स्कूली बच्चों को रोग से बचाव व नियंत्रण के विषय में बताया जाएगा।

दिमागी बुखार सबसे अधिक नवजात शिशुओं से लेकर 15 वर्ष के बच्चों को प्रभावित करता है। इन्हें बेहतर स्वास्थ्य देना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे ये बच्चे आने वाले कल के लिए देश व प्रदेश के विकास में सहभागी बन सकें। ■

औद्योगिक क्रान्ति की ओर पहला कदम इन्वेस्टर्स समिट

लखनऊ में आयोजित होने वाला 'यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट' प्रदेश में औद्योगिक क्रान्ति की ओर पहला कदम है। इसके बाद निश्चित तौर पर प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनेगा तथा निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

शुक्रवार को अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी से मिले और उन्हें इस वर्ष का ऐतिहासिक जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हुए 'इन्वेस्टर्स समिट' हेतु आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने रेलवे और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल जी तथा कपड़ा और सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी से भी मुलाकात करके उन्हें 'इन्वेस्टर्स समिट' में शामिल होने का आमंत्रण दिया।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने निवेशकों के हित में नवीन औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017, अन्य निवेशोन्मुख नीतियों के प्राविधान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा सिंगल विण्डो पोर्टल जैसे कई कदम उठाये हैं, जिससे निवेशकों को प्रदेश में अपने उद्यम स्थापित करने में कोई असुविधा न हो।

इस समिट के प्रति समूचे देश ही नहीं वरन् विदेशों के निवेशकों में भी भारी उत्साह देखा गया है और देश–विदेश के प्रतिष्ठित निवेशक इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने रोजगार की समस्या को गंभीरता से लेते हुए पहली बार निवेश के साथ ही रोजगार सृजन पर भी समान रूप से बल दिया है। इससे राज्य में उपलब्ध जनबल को काम मिलेगा तथा व्यापक सामाजिक व आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा। ■

ब्रिटेन के निवेशकों को आमंत्रण

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ ने मुलाकात कर ब्रिटेन और उत्तर प्रदेश के बीच सम्पर्क बढ़ाने, अवस्थापना व औद्योगिक विकास, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उद्यमों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की गई हैं, जिनमें उद्यमों की स्थापना के लिए आकर्षक प्राविधान हैं। इन्वेस्टर्स समिट में प्रतिभाग करने के लिए ब्रिटेन के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए उन्होंने उच्चायुक्त को प्रयाग कुम्भ–2019 का 'लोगो' भी भेंट किया।

शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहन

इलेक्ट्रिक वाहन देश की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं : मुख्यमंत्री

पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से स्तरीय होने के कारण इनका भविष्य सम्भावनाओं से भरा है

राज्य सरकार शहरी इलाकों में निजी क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करेगी

इलेक्ट्रिक वाहन देश की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता के लिए इन्हें तकनीकी रूप से और सक्षम होना पड़ेगा। समाज में स्वीकार्यता के लिए इन्हें सरल, सस्ता और सुगम बनाए जाने की भी आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के एक शुभारम्भ कार्यक्रम में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शीत ऋतु के दौरान प्रमुख शहरों में पर्यावरण प्रदूषण की अधिकता के कारण स्मॉग की समस्या सामने आयी है, जिसके समाधान में इलेक्ट्रिक वाहन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन वाहनों के संचालन से डीजल, पेट्रोल आदि के आयात पर व्यय होने वाली धनराशि बचेगी, जिसका उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकता है।

21 व 22 फरवरी को प्रदेश में आयोजित हो रही इन्वेस्टर्स समिट का एक फोकस सेक्टर इलेक्ट्रिक वाहन भी हैं। इस सेक्टर में उद्यमियों ने अपनी रूचि दिखायी है। राज्य सरकार आगरा–दिल्ली के बीच में इन वाहनों को प्रमोट करने के साथ ही, प्रदेश के अन्य स्थानों में भी इन्हें बढ़ावा देना चाहती है। लखनऊ शहर में शीघ्र ही 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। राज्य सरकार शहरी इलाकों में निजी क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करेगी। ■

इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए 01 अप्रैल, 2015 से फेम इण्डिया योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना के तहत वर्ष 2020 तक देश की सड़कों पर 60 से 70 लाख इलेक्ट्रिक/हाईब्रिड वाहनों के संचालन का लक्ष्य है।

दिव्यांगजनों के पुनर्वासन एवं सशक्तिकरण के प्रति प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान के लिए कृतसंकल्प है। दिव्यांगजनों के पुनर्वासन एवं सशक्तिकरण के प्रति भी प्रदेश सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान और बुजुर्ग सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। सरकार 'सबका साथ–सबका विकास' की भावना से प्रदेश के सभी वर्गों और क्षेत्रों का विकास कर रही है। मुख्यमंत्री ने जनपद रामपुर में गांधी स्टेडियम मैदान में आयोजित दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण/ कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम में यह उद्गार व्यक्त किए।

दिव्यांजनों को उपकरणों का वितरण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम के आयोजन हेतु भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए 3319 सहायक उपकरणों से लाभान्वित होने वाले सभी 2211 दिव्यांगजनों को बधाई दी। वितरित सहायक उपकरणों में ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, दृष्टि बाधितों के लिए स्मार्ट केन, डेजी प्लेयर, टैबलेट तथा श्रवणबाधितों के लिए कान की डिजिटल मशीन और कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के दिनचर्या में सहायक ए.डी.एल. किट, मोबाइल फोन आदि शामिल हैं।

दिव्यांजनों को प्रोत्साहन पर दिया जोर

योगी जी ने कहा कि इन सहायक उपकरणों के माध्यम से दिव्यांगजन का जीवन पहले से बेहतर, सरल और सहज होगा। वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर सकेंगे। उन्होंने दिव्यांगजन को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ईश्वर प्रदत्त कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए वे अपनी प्रतिभा एवं संकल्प के बल पर समाज में अपने कार्यों से प्रेरक बनें। दिव्यांगता मनुष्य के लिए एक प्रकार की परीक्षा है, परन्तु दिव्यांगजन इसे स्वीकार कर अपनी प्रतिभा से विभिन्न क्षेत्रों में नये कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए दिव्यांगजन प्रोत्साहन के हकदार हैं। समाज की संवेदना इनके साथ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में विशिष्ट प्रतिभा होती है, जिसे प्रोत्साहित किए जाने पर वह समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

राज्य सरकार दिव्यांगजनों के पुनर्वासन हेतु अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। उन्हें सशक्त बनाते हुए समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बाधारहित वातावरण एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के कार्य भी कर रही है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन की पेंशन धनराशि को 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

हर वर्ग की तरक्की, हर तबके का विकास

मुख्यमंत्री जी ने रामपुर में पुनः दोहराया कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, कमजोर, वंचित व नौजवान के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार प्रदेश की 22 करोड़ जनता का बिना किसी भेदभाव के विकास कर रही है। जो काम पूर्ववर्ती सरकारें विगत वर्षों में नहीं कर पायीं, वह वर्तमान सरकार ने 10 माह में करके दिखाया है। सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान हेतु विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं को पूरी तत्परता से संचालित कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार आमजन को बेहतर कानून व्यवस्था, अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण सृजित करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है।

> विकास 22 करोड़ जनता का अधिकार है, किन्तु किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। सरकार 'सबका साथ-सबका विकास' के अन्तर्गत सभी वर्गों की कल्याण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों से जनता में उत्साह

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के फसली ऋण मोचन के ऐतिहासिक निर्णय के अन्तर्गत लघु व सीमान्त किसानों के एक लाख की सीमा तक का ऋण माफ किया गया है, जिससे प्रदेश के 86 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए है।

वर्ष 2022 तक प्रदेश के **किसानों की आमदनी को दोगुनी** किये जाने हेतु रोडमैप तैयार किया गया है। साथ ही वर्ष 2022 तक **सभी गरीब परिवारों को मकान** उपलब्ध कराने की योजना है।

सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से लाभार्थियों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गए हैं।

प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के तहत बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया गया है। विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

सीरगोवर्धन का तीर्थ स्थल के रूप में विकास होगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहा कि हमें अपने संतों–महात्माओं के योगदान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उनकी मानव समाज के प्रति श्रद्धा को प्रचारित करना चाहिए। बुद्धवार को वाराणसी में महान संत रविदास जी की 641वीं जयंती के अवसर पर सीरगोवर्धन स्थित रविदास मंदिर में उन्होंने दर्शन–पूजन कर सत्संग पण्डाल में श्रद्धालुओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि संत रविदास जी ने लोगों को सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए समाज को जागरूक किया। वे समता और सदाचार को अत्यन्त महत्व देते थे। 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' के अपने कथन के माध्यम से उन्होंने आंतरिक पवित्रता और निर्मलता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मानव–मानव में भेद नहीं होना चाहिए। हम सब का एक ही भाव है कि हम सब इस भारत के वासी है और भारत सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा व खुशहाल होगा, तभी हम सब खुशहाल होंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कहीं जाते हैं, तो उनका बहुत सम्मान होता है। अमेरिका जाते हैं, तो पूरा अमेरिका स्वागत के लिए उमड़ पड़ता है। चीन और जापान में स्वागत होता है। अमेरिका, चीन आदि देशों में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का उदाहरण दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह विकास के लिए काम कर रहे है, उसी प्रकार हम सभी को भी काम करना है। ■

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अनुसार रविदास जयंती पर स्कूलों में रविदास जयंती का आयोजन करके संत रविदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को उनके बारे में जानकारी मिले और वे उनकी शिक्षा से परिचित हो सकें। उनकी जयंती पर अवकाश नहीं होना चाहिए।

भारत की योग परम्परा को संतो ने पूरी दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया है। योग के चमत्कार को अब यूनेस्को भी मानता है।

भारत सुरक्षित, समृद्ध व खुशहाल होगा, तभी हम सब खुशहाल होंगे।

> जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सीरगोवर्धन के विकास का नया खाका खींचकर, इसके सुन्दरीकरण के लिये योजना बनाकर शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इसको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जायेगा।
>
> **–योगी आदित्यनाथ**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 06 फरवरी 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

राजस्व संहिता विधेयक-2018 से दूर होंगी निवेशकों की समस्याएं

उद्यमों की स्थापना में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए इन्वेस्टर्स समिट से पूर्व ही प्रदेश सरकार ने राजस्व संहिता विधेयक-2018 के मसौदे को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस विधेयक में औद्योगिक निवेश हेतु जमीन सुगमता से उपलब्ध होने और सीलिंग से जुड़े प्रावधानों को सरल बनाया गया है। संहिता के तहत अब कोई भी भूमिधर कान्ट्रैक्ट पर अपनी जमीन दे सकेगा। इससे बुंदेलखड जैसे क्षेत्रों में कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं हो रही भूमि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पट्टे पर दी जा सकेगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिजली परियोजनाओं में वृद्धि होगी।

अविवाहित पौत्री को मिलेगा पैतृक संपत्ति में हक

महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए योगी सरकार ने पैतृक संपत्ति में हक दिलाने के लिए राजस्व संहिता में नए संशोधन प्रस्तावित किए हैं। किसी खातेदार की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति पर उसके मृतक पुत्र की अविवाहित पुत्री को भी पुत्र के समान उत्तराधिकार देने के लिए संशोधन का प्रस्ताव है। इस आशय का बदलाव होने पर किसी निःसंतान पुरूष या महिला खातेदार की मृत्यु होने पर उसकी अविवाहित भतीजी या भांजी को संपत्ति में उत्तराधिकार मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

कीटनाशकों के उपयोग पर अनुदान

किसानों के हित में सरकार फसल को कीड़े-मकोड़ो से बचाने के लिए प्रयुक्त होने वाले कीटनाशकों पर अनुदान देगी। इस कदम से फसल को नुकसान कम होगा तथा किसानों की आय बढ़ेगी। बॉयोपेस्टीसाइड व बीज शोधक रसायनों के उपयोग पर सरकार ने 75 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। लघु तथा सीमान्त किसानों हेतु कृषि रक्षा रसायनों, कृषि रक्षा यंत्रों तथा बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान होगा।

मिट्टी खनन नियमावली में संशोधन

उ.प्र. उपखनिज (परिहार) नियमावली में संशोधन का निर्णय भी लिया गया है। इस संशोधन से केन्द्र तथा राज्य सरकार की निर्माण एजेन्सियों को परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने हेतु मिट्टी के खनन का अधिकार मिल सकेगा। इससे विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में सहायता मिलेगी।

खादी से मिलेगा ग्रामीणों को रोजगार

ग्रामोद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार ने **खादी एवं ग्रामोद्योग विकास तथा सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति** को सहमति प्रदान की है। खादी तथा ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना तथा कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना सरकार का इस नीति का प्रमुख लक्ष्य है।

नीति के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना प्रक्रिया का सरलीकरण होगा और इन इकाईयों को पूर्वांचल, मध्यांचल तथा बुन्देलखण्ड में स्टांप शुल्क पर 100 प्रतिशत तथा पश्चिमांचल में 75 प्रतिशत तक की छूट की व्यवस्था है। इस नीति में जीएसटी के तहत राज्यांश की सीमा तक जमा कराई गई धनराशि के बराबर रकम की प्रतिपूर्ति की भी प्राविधान है।

पूर्व सैनिकों की पेंशन 4 हजार से बढ़ाकर 15 हजार

पोल्ट्री फार्म के लिए बीपीएल को सहायता

मनोरंजन कर विभाग के 377 कर्मचारियों का वाणिज्य कर विभाग में विलय

ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से नहीं होगी शराब की तस्करी

कैबिनेट ने शराब की तस्करी रोकने के लिए शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के अन्तर्गत शराब के उत्पादन एवं निकासी की व्यवस्था को इलेक्ट्रानिक माध्यम से ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली से नियंत्रित किये जाने की व्यवस्था होगी।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक श्री अनुज कुमार झा द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी